



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2010/अग्रहायण 29, 1932

No. 314]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2010/AGRAHAYANA 29, 1932

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2010

विषय : यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एनिलिन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत।

सं. 14/39/2010-डीजीएडी.—यतः मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं. लि. (जिसे एतदपश्चात् आवेदक कहा जाएगा) ने 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा जाएगा) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण क्षति निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिन्हे एतदपश्चात् नियम कहा जाएगा) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें उन्होंने यूरोपीय संघ (जिसे एतदपश्चात् "संबद्ध भूभाग" कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एनिलिन (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया है और संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु पाटनरोधी जाँच शुरू किए जाने का अनुरोध किया है। मै. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. ने इस आवेदन का समर्थन किया है।

2. और यतः प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं और वे एतद्वारा किसी कथित पाटन की उपस्थिति, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे यदि लागू किया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन एवं परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जाँच प्रारंभ करते हैं।

## विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद "एनिलिन" है। एनिलिन को "एनिलिन तेल" के नाम से भी जाना जाता है (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है)। एनिलिन एक पारदर्शी तैलीय द्रव है और एक प्राथमिक एमीन यौगिक है। आसवन की प्रक्रिया के तुरंत बाद इसका रंग परिवर्तित होकर हल्का फीका पीला और प्रकाश या हवा के सम्पर्क में आने पर गहरा हो जाता है।

4. संबद्ध वस्तु का व्यापक उपयोग औषधि, भेषजों, रंजकों तथा रंजक मध्यवर्ती जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में मूलभूत कार्बनिक रसायन अनिवार्य तत्व के रूप में होता है। एनिलिन का प्रयोग रबड़ रसायन, विस्फोटक, रेजिन आदि जैसे कुछ अन्य उद्योगों में भी होता है। संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 में सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 2921.41 के अंतर्गत वर्गीकृत है।

### घरेलू उद्योग तथा उसका मत

5. यह आवेदन मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं. लि. द्वारा दायर किया गया है और मै. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. ने इसका समर्थन किया है। देश में संबद्ध वस्तु के केवल तीन ज्ञात उत्पादक हैं। आवेदन में दी गई सूचना के अनुसार अप्रैल, 09- जून, 10 के दौरान भारतीय उत्पादन में मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं. लि. का हिस्सा 77% रहा है और समर्थक के साथ भारतीय उत्पादन में उसका हिस्सा लगभग 90% बनता है। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक “घरेलू उद्योग” है।

6. उपर्युक्त की जांच के बाद प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि नियम 2 के अर्थ के भीतर आवेदक घरेलू उद्योग है और उपर्युक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार स्थिति संबंधी मानदण्ड को पूरा करता है।

### शामिल देश

7. वर्तमान जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ के भूभाग में स्थित सभी देश हैं।

### समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एनिलिन एवं संबद्ध भूभागों द्वारा आयातित एनिलिन में कोई ज्ञात विशेष अंतर नहीं है। भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मानदण्डों के संदर्भ में दोनों उत्पादों की विशेषताएँ तुलनीय हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उनकी विशेषताएँ समतुल्य हैं। यह भी दावा किया गया है कि उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर करते हैं। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध भूभाग से आयातित संबद्ध वस्तुओं के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

### सामान्य मूल्य

9. यूरोपीय संघ में घरेलू बिक्री के संबंध में आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण आवेदक ने संबद्ध भूभाग में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्ट्या आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए परिकलित मूल्यों

के आधार पर संबद्ध भूभाग से संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर विचार किया है और जाँच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा उसी पर विचार किया गया है।

### निर्यात कीमत

10. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय सूचना सेवा (आईबीआईएस), मुम्बई से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर किया गया है। विभिन्न कारकों के लिए कीमत समायोजन का दावा किया गया है परन्तु सामान्यतः प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने वाले केवल समुद्री बीमा एवं समुद्री भाड़ा के घटकों का समायोजन करके उसे उचित सीमा तक घटाया गया है। संबद्ध भूभागों से संबद्ध वस्तु के लिए आवेदक द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

### पाटन मार्जिन

11. संबद्ध भूभाग के संदर्भ में सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वारा स्तर पर की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद है कि यूरोपीय संघ के भूभाग में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखाना द्वारा निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

### क्षति एवं कारणात्मक संबंध

12. आवेदक ने दावा किया है कि जैसाकि नीचे दर्शाया गया है, घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से इतर कारकों से क्षति नहीं हुई है : -

क. संबद्ध वस्तु के कुल आयातों में से लगभग 50% आयात संबद्ध भूभाग से होता है और 20% आयात उन देशों से होता है जिन पर पहले से पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। अन्य देशों से आयातों की मात्रा एवं मूल्य या तो न्यूनतम से कम है अथवा निर्यात कीमत अधिक है अथवा उन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है।

ख. वर्ष 2008-09 को छोड़कर संबंधित उत्पाद की माँग में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। वर्ष 2008-09 में माँग में कमी आने का एकमात्र कारण वैश्विक मंदी होने का दावा किया गया है।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी, विश्वभर के अन्य उत्पादनकर्ताओं द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी के साथ तुलनीय है और संबंधित उत्पाद के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. संबंधित उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ड. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिसका घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान रहा हो ।

च. घरेलू उद्योग अधिकाँश बिक्री घरेलू बाजार में ही करता है और उसके निर्यात की मात्रा बहुत कम है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एकमात्र कारण घरेलू प्रचालनों में कमी आना है।

छ. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

ज. संबद्ध भूभाग से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों का हास एवं अवमूल्यन हुआ है और यदि पाटन न होता तो उसमें संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप ही वृद्धि हुई होती।

झ. पाटित आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग में गिरावट आई है जिससे प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव का निर्धारण होता है।

ट. लाभ, निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में अत्यधिक गिरावट प्रदर्शित हुई है।

13. इस बात के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं कि संबद्ध भूभाग से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वार्तविक क्षति हुई है।

### पाटनरोधी जांच की शुरूआत

14. उपर्युक्त पैराग्राफों के मदेनजर प्राधिकारी संबद्ध भूभाग के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव की जांच करने हेतु पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

### जांच की अवधि

15. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2009 से 30 जून, 2010 (15 माह) है। तथापि क्षति जांच अवधि में वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

### सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है : -

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**  
**वाणिज्य विभाग**  
**भारत सरकार**  
**कमरा नं. 243, उद्योग भवन**  
**नई दिल्ली-110107**

17. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वर्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं तथा प्रतिनिधिक उपभोक्ता संगठनों को भी अवसर प्रदान कर रहे हैं जो पाटन, क्षति तथा कारणात्मकता से संबंधित जांच से संगत सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

#### समय सीमा

18. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन) के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों जिन्हें अलग से लिखा गया है, को यह सूचना उन्हें भेजे गए पत्र की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन) के भीतर भेजनी होगी।

19. नियमावली के नियम 6(7) के संदर्भ में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

#### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

20. नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय सारांश वाली उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

५८२३९/१०-२

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****Initiation Notification**

New Delhi, the 20th December, 2010

**Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Aniline originating in or exported from European Union.**

**No. 14/39/2010-DGAD.**— Whereas M/S Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited. (herein after referred to as applicant) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (herein after referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as the Rules), alleging dumping of Aniline, (hereinafter referred to as subject goods), originating in or exported from European Union, (herein after referred to as “Subject Territory”) and requested for initiation of Anti Dumping investigations for levy of anti dumping duties on the subject goods. The request is supported by M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd.

2. AND WHEREAS, the Authority finds sufficient *prima facie* evidence of dumping of the subject goods from the subject Territory, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**Product Under Consideration**

3. The product under consideration is ‘**Aniline**’. Aniline is also known as “**Aniline Oil**” (hereinafter also referred to as ‘**subject goods**’). Aniline is a transparent, oily liquid and is a primary amine compound. Its colour transforms to light pale yellow liquid when freshly distilled and darkens when exposed to light or air.

4. Subject goods are extensively used as a basic organic chemical essential for vital industries such as drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates. Aniline is also used in some other industries such as rubber chemicals, explosives, resins, etc. The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under custom sub-heading no. 2921.41.

### **Domestic Industry and Standing**

5. The application has been filed by M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited and supported by M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited. There are only three known producers of the subject goods in the Country. According to the information provided in the application, the production of Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited constitute 77% of Indian production during Apr'09-June'10 and along with the supporter, it constitutes about 90% of the Indian Production. Thus, the applicant shall constitute "domestic industry" for the purpose of the present investigations.

6. The Authority, after examining the above, determines that the applicant constitutes domestic Industry within the meaning of the Rule 2 and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

### **Countries Involved**

7. The countries involved in the present investigation are all the countries situated within the territory of European Union.

### **Like Article**

8. Applicant has claimed that there is no significant difference in the Aniline produced by the applicant and the Aniline exported from subject Territories. Both products are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Both the products are technically and commercially substitutable and hold closely resembling characteristics. It is further claimed that the consumers have used the two interchangeably. Therefore, for the purpose of present investigation, subject goods produced by the applicant are being treated as "like Article" to the subject goods imported from subject territory within the meaning of the Anti Dumping Rules.

### **Normal Value**

9. In the absence of availability of data in respect of the domestic sales in European Union, the applicant has constructed normal value on the basis of constructed cost of production of subject goods in subject Territory. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject territory on the basis of constructed values as made available by the applicant, and the same has been considered by the Authority for the purpose of initiation.

### **Export Price**

10. The export price of the subject goods from the subject Countries has been claimed on the basis of data obtained from International Business Information Services (IBIS), Mumbai. Price Adjustments have been claimed on account of various factors but have been scaled down to reasonable limits by adjusting the components of Ocean Freight and Marine

4823 46) 10-3

Insurance alone, normally adopted by the Authority. There is sufficient evidence of export prices claimed by the applicant for the subject goods from the subject countries.

### **Dumping Margin**

11. Normal value and export price have been compared at ex-factory level in respect of the subject territory. There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the territory of European Union, so arrived is significantly higher than the ex-factory export price indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped by exporters from subject countries into the Indian market.

### **Injury and Causal Link**

12. The applicant has claimed that injury to the domestic industry has not been caused due to the factors other than the dumped imports, as shown below:

- a. Nearly 50% of the total imports of the subject goods primarily take place from the subject territory and another 20% is imported from countries already attracting Anti-Dumping Duty. Volume and value of imports from other countries are either de-minimis, or the export price is higher or are attracting anti dumping duties.
- b. Demand of the product concerned has shown a positive trend except for the year 2008-09. This is claimed to be solely as a result of global recession.
- c. The technology adopted by the Domestic Industry is comparable to the technology adopted by other players across the world and the technology for producing the product concerned has not undergone any change.
- d. There has been no change in the pattern of consumption for the product concerned.
- e. There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the Domestic Industry.
- f. Domestic Industry is substantially involved in the domestic market and maintains very less export volumes. The injury to the Domestic Industry is contended solely on account of deterioration in domestic operations
- g. Imports are undercutting the prices of the Domestic Industry.
- h. Due to dumped imports from the subject territory, prices of the Domestic Industry are depressed and suppressed, and but for dumping the same would have increased in line with the increase in the cost of production of the subject goods.
- i. Production, sales and capacity utilization has shown decline as a result of increase in dumped imports, thus establishing adverse volume effect.
- j. Performance of the Domestic Industry in terms of profit, return on investment and cash flow has shown material deterioration.

13. There is sufficient *prima-facie* evidence that the dumped imports of subject goods from subject countries are, *prima facie*, causing material injury to the domestic industry.

### **Initiation of Antidumping Investigation**

14. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject Territory.

### **Period Of Investigation**

15. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1<sup>st</sup> April 2009 to 30<sup>th</sup> June 2010 (15 months). The injury investigation period will, however, cover the period 2006-07, 2007-08, 2008-09 and the POI.

### **Submission of Information**

16. The exporters in the subject Countries, their Government through the Embassy, the importers in India known to be concerned with this investigation and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

The Designated Authority  
 Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,  
 Ministry of Commerce & Industry,  
 Department of Commerce,  
 Government of India,  
 Room No. 243, Udyog Bhavan,  
 New Delhi – 110107.

17. As per Rule 6(5) of the Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation and to representative consumer organizations, who can furnish information relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

### **Time Limit**

18. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

### **Submission of Information**

19. In terms of Rule 6(7) of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided. In case where an

interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

**Inspection of Public File**

20. In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by the interested parties.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority